

Daily Current Affairs

Date : 18 May, 2026

UTKARSH
CLASSES

CIVIL
SERVICES

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'ग्राम रथ अभियान' का समापन
2.	SASCI पहल के तहत राज्य को ₹11,000 करोड़ तक की सहायता
3.	RUHS द्वारा 'टीचर्स वेलफेयर फंड रेग्यूलेशन - 2026' लागू
4.	'कोटा डोरिया' और 'एरी सिल्क' से फैब्रिक विकसित करने हेतु पहल
5.	RAJ PAHAL (पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग)
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. NSO का 'अनिगमित सेक्टर के लिए वार्षिक सर्वेक्षण' में राजस्थान 2. नीदरलैंड में 'पधारो म्हारे देस' से प्रधानमंत्री का स्वागत 3. चर्चा में पाली का 'प्रवासी प्रकोष्ठ'
7.	'राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और अविनियमन' पहल
8.	सुखदेव थापर (1907 - 1931)
9.	बांध पुनर्संरचना और सुरक्षा आधुनिकीकरण: भारत
10.	निर्वाह मजदूरी (Living Wage)
11.	भारत और संयुक्त अरब अमीरात
12.	चाबहार बंदरगाह
13.	अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के कारण प्रदूषण
14.	पांचवीं पीढ़ी का उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA)
15.	'अभय': एआई-संचालित सत्यापन प्रणाली

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



'ग्राम रथ अभियान' का समापन



चर्चा में क्यों?

- 16 मई, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के ठिकरिया (बगरू) गाँव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में आयोजित 'ग्राम रथ अभियान' के समापन समारोह को संबोधित किया।

ग्राम रथ अभियान
27 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ

'ग्राम-2026' आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए

- 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान
- 183 ग्रामीण बहुल विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे ग्राम रथ
- प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों में जन-जागरूकता कार्यक्रम

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान [f](#) [i](#) [X](#) [v](#) /DIPRRajasthan

--2--



मुख्य बिन्दु:

- 'ग्राम रथ अभियान' का शुभारंभ : हरीश चंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (HCM RIPA), जयपुर से।
- आयोजन : 27 अप्रैल से 16 मई, 2026 तक।
- यह एक 15 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की 183 विधानसभा क्षेत्रों में 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026' का प्रचार करना और किसानों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।
- साथ ही, कृषि, पशुपालन, डेयरी और ग्रामीण विकास सहित 13 प्रमुख विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाना भी इसका प्राथमिक लक्ष्य था।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

ग्राम विकास चौपालों में मुख्यमंत्री :

- 15 दिवसीय 'ग्राम रथ अभियान' के तहत मुख्यमंत्री ने राज्य में कई ग्राम विकास चौपालों और ग्राम उत्थान शिविरों में भाग लिया है।

प्रमुख दौरे :

- प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गाँव में।
- सीकर जिले के खंडेला (जाजोद गाँव) में।
- पुष्कर (अजमेर) के कड़ैल गाँव में।
- ओसियां (जोधपुर) के मंडियाई खुर्द गाँव में।
- जालौर के पंसेरी गाँव में।

SASCI पहल के तहत राज्य को ₹11,000 करोड़ तक की सहायता

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान को केंद्र सरकार की 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2026-27' के तहत ₹11,000 करोड़ तक की ब्याज मुक्त ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।

केंद्र सरकार की SASCI पहल के तहत राज्य को 11 हजार करोड़ रुपये तक की ब्याज मुक्त सहायता



मुख्य बिन्दु:

- इस पहल के तहत वर्ष 2025-26 में राज्य को ₹10,547.88 करोड़ प्राप्त हुए थे।
- उद्देश्य** : राज्य में पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण और बुनियादी विकास कार्यों को गति देना।
- परियोजना की लागत** : इस राशि का उपयोग राज्य में ₹5 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली बड़ी पूंजीगत परियोजनाओं एवं आधारभूत विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। जिससे आधारभूत संरचना निर्माण, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार एवं भविष्य की उत्पादक क्षमता को मजबूती मिलेगी।

Daily Current Affairs

Date : 18 May, 2026



SACSI पहल के बारे में :

- **शुरुआत** : केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से संचालित।
- **संबंधित विभाग** : व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)
- योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व' आधार पर जारी की जाती है।
- पहल के अंतर्गत राज्यों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- पहल के तहत विभिन्न मंत्रालयों (जैसे - पर्यटन और खान मंत्रालय) के माध्यम से राज्यों में बुनियादी ढांचे और सुधारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--5--

RUHS द्वारा 'टीचर्स वेलफेयर फंड रेग्यूलेशन - 2026' लागू



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) द्वारा अपने शिक्षकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'टीचर्स वेलफेयर फंड रेग्यूलेशन - 2026' लागू किए गए।



RUHS द्वारा 'टीचर्स वेलफेयर फंड रेग्यूलेशन - 2026' लागू

--:6:--

Daily Current Affairs

Date : 18 May, 2026



मुख्य बिन्दु:

- इस रेग्यूलेशन के तहत RUHS के संघटक और संबद्धता प्राप्त 597 मेडिकल संस्थानों के लगभग 10,700 शिक्षकों को कवर किया गया है।
- इसके तहत गंभीर बीमारी, दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती होने और असामयिक मृत्यु की स्थिति में शिक्षकों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

रेग्यूलेशन के मुख्य प्रावधान:

- **असामयिक मृत्यु पर सहायता** : किसी शिक्षक की असामयिक मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस को ₹3 लाख की वित्तीय सहायता।
- **गंभीर बीमारी के इलाज के लिए** : हृदय रोग, कैंसर, पैरालिसिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS), किडनी और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ₹1 लाख तक की सहायता।
- **दुर्घटना या गंभीर चोट पर** : किसी भी दुर्घटना या गंभीर चोट लगने की स्थिति में ₹50 हजार तक की आर्थिक सहायता।
- **अस्पताल में भर्ती होने पर** : सामान्य तौर पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में ₹30 हजार तक की सहायता।

--7:--

'कोटा डोरिया' और 'एरी सिल्क' से फैब्रिक विकसित करने हेतु पहल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने राजस्थान के पारंपरिक कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध एरी सिल्क को मिलाकर एक नया प्रीमियम फ्यूजन फैब्रिक विकसित करने की पहल शुरू की।



मुख्य बिन्दु:

- इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य देश की दो सबसे समृद्ध हथकरघा परंपराओं को एक साथ लाकर वैश्विक और घरेलू उच्च-स्तरीय बाजारों को लक्षित करना है।

--8--

Daily Current Affairs

Date : 18 May, 2026



- **MoU पर हस्ताक्षर** : इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के जिला उद्योग केंद्र (DIC) और पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (NEHHDC) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- यह पहल प्रधानमंत्री के 5F विजन के अनुरूप है। 5F विजन - फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (कोटा डोरिया):

- कोटा डोरिया साड़ियों को परंपरागत रूप से मंसूरिया साड़ियों के नाम से जाना जाता है।
- अपनी विशिष्ट पहचान और पारंपरिक हस्त बुनाई के लिए कोटा डोरिया को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में भौगोलिक संकेतक (GI टैग) भी प्रदान किया जा चुका है।
- कोटा जिले के कैथून कस्बे में स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) विश्व प्रसिद्ध कोटा डोरिया साड़ी के संरक्षण, विकास और स्थानीय बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक प्रमुख केंद्र है।

--9--

RAJ PAHAL (पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, गडरिया-गाड़री- गायरी-धनगर-पाल-बघेल सहित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

स्कूल ऑन व्हील्स शिक्षा पहुंचेगी हर वंचित तक

→ आगामी वर्ष RAJ PAHAL (PORTABLE ACCESS FOR HOLISTIC AND ASSISTED LEARNING) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

→ प्रत्येक जिले में एक SCHOOL ON WHEELS स्थापित किया जाएगा।

मुख्य बिन्दु:

- इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पुण्यश्लोक अहल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन किया।

- साथ ही, मुख्यमंत्री द्वारा 'खानवा के युद्ध' में राणा सांगा के साथ मुगल आक्रांताओं के खिलाफ अदम्य साहस, शौर्य, स्वामीभक्ति का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले वीर सिंह बघेल का भी विशेष जिक्र किया गया।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

RAJ PAHAL तथा 'स्कूल ऑन व्हील्स' कार्यक्रम :

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में सरकार द्वारा घुमन्तू एवं अर्द्ध-घुमन्तू समुदाय; यथा-गाड़िया लोहार, बंजारा एवं मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए 'RAJ PAHAL (पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग)' तथा 'स्कूल ऑन व्हील्स' कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई। ।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य

- शिक्षा से वंचित बच्चों तक पहुँच : गाड़िया लोहार, बंजारा और दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे जो नियमित स्कूल नहीं जा पाते, शिक्षा को सीधे उनके निवास स्थान तक पहुँचाना।
- हाशिए के समुदायों का सशक्तीकरण : सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों, आत्मविश्वास और संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करना।
- ड्रॉप-आउट दर में कमी : पलायन के कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने (Drop-out) की समस्या को समाप्त करना।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>NSO का 'अनिगमित सेक्टर के लिए वार्षिक सर्वेक्षण' में राजस्थान</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी 'गैर-निगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण' (ASUSE) में राजस्थान आठवें पायदान पर रहा।सर्वेक्षण के अनुसार, प्रदेश में 41.45 लाख प्रतिष्ठान संचालित हैं। देश में ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या 7.92 करोड़ है, जिनमें राजस्थान की हिस्सेदारी 5.23 प्रतिशत है।शीर्ष 8 राज्य : उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान।
2.	<p>नीदरलैंड में 'पधारो म्हारे देस' से प्रधानमंत्री का स्वागत</p> <ul style="list-style-type: none">प्रवासी भारतीयों द्वारा राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत 'पधारो म्हारे देस' से नीदरलैंड के द हेग शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया।
3.	<p>चर्चा में पाली का 'प्रवासी प्रकोष्ठ'</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, पाली जिला प्रशासन द्वारा "आओ गाँव चलें" अभियान के तहत एक विशेष प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।इसका उद्देश्य देश-विदेश में बसे पाली के प्रवासियों को अपने पैतृक गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और पर्यावरण संरक्षण जैसे जनहित कार्यों से जोड़ना है।यह राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से सामाजिक जनभागीदारी को मजबूत करता है।



राष्ट्रीय परिदृश्य



'राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और अविनियमन' पहल



चर्चा में क्यों?

- त्रिपुरा 'राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और अविनियमन (National Compliance Reduction and Deregulation) पहल के अविनियमन चरण-II के सभी प्राथमिक क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है।



मुख्य बिन्दु:

- किसी उद्योग या क्षेत्रक पर से सरकारी निगरानी या नियंत्रण को कम करना या समाप्त करना अविनियमन कहलाता है।

राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और अविनियमन पहल

- **शुरुआत:** कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 2025 में अनुपालन न्यूनीकरण और अविनियमन पर एक कार्यबल का गठन किया गया था।
- **उद्देश्य:** अनावश्यक या पुराने नियमों की पहचान करना और उनके सरलीकरण की सिफारिश करना; न्यूनतम विनियमन के सिद्धांतों के अनुरूप कानूनों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करना।
- टास्क फोर्स ने 5 व्यापक क्षेत्रकों में 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों की पहचान की थी।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों को कवर करने के लिए जनवरी 2026 में चरण-II शुरू किया गया था, जिसमें भूमि, भवन और निर्माण, उपयोगिताएं और अनुमतियां, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल, श्रम और व्यापक सुधार शामिल हैं।

इतिहास एवं संस्कृति

सुखदेव थापर (1907 - 1931ई.)

चर्चा में क्यों?

- 15 मई को शहीद सुखदेव थापर की जयंती मनाई गई।

मुख्य बिन्दु:

सुखदेव थापर

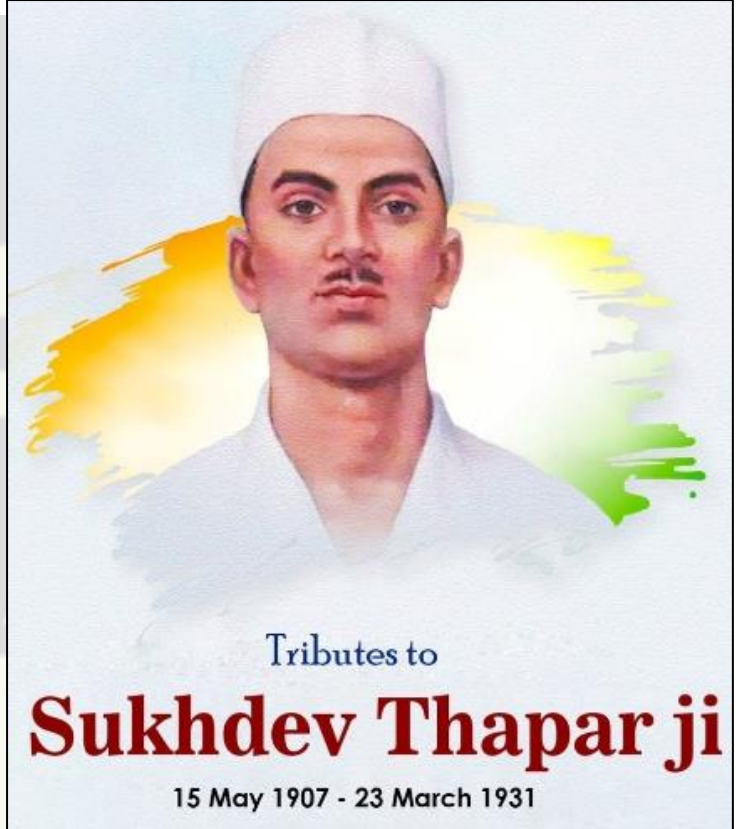
- उनका जन्म लुधियाना (पंजाब) में हुआ था।

प्रमुख योगदान:

- उन्हें 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA) का एक प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है।

- ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे.पी. सांडर्स की हत्या (लाहौर षड्यंत्र केस) में शामिल होने के कारण उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ गिरफ्तार किया गया था।

- उन्हें 23 मार्च, 1931 को लाहौर जेल में शहीद भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।





भूगोल एवं भू-विज्ञान



बांध पुनर्संरचना और सुरक्षा आधुनिकीकरण: भारत



चर्चा में क्यों?

- भारत विश्व के सबसे बड़े 'बांध पुनर्संरचना और सुरक्षा आधुनिकीकरण' कार्यक्रमों में से एक संचालित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुरानी जल अवसंरचना को मजबूत और सुरक्षित बनाना है।



मुख्य बिन्दु:

भारत में बांधों की स्थिति

- **विश्व में तीसरा स्थान:** भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बांध नेटवर्क है। प्रथम दो स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। भारत में बांधों की कुल संख्या 6,628 है।
- **राज्य सरकारों के स्वामित्व में:** भारत में लगभग 98.5% बांधों का स्वामित्व राज्य सरकारों के पास है।
- **सर्वाधिक बांध:** भारत में बांधों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में हैं।

भारत में बांधों की सुरक्षा से संबंधित मुख्य चिंताएँ

- **पुराना होना:** इनमें से लगभग 26% बांध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- **तलछट जमा होना:** जलाशयों ने तलछट जमाव के कारण अपनी सकल भंडारण क्षमता का औसतन 19% खो दिया है।
- **विवर्तनिकी गतिविधि:** उदाहरण के लिए, 2001 में भुज (गुजरात) में आए भूकंप के बाद चांग बांध की नींव की मिट्टी कमजोर हो गई थी।

Daily Current Affairs

Date : 18 May, 2026



- **हिमनदीय झील प्रस्फोट जनित बाढ़ (GLOF):** उदाहरण के लिए, 2023 में हिमनदीय झील के टूटने से आई अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के दौरान चुंगथांग बांध (सिक्किम) बह गया था।
- **अन्य चिंताएँ:** हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न में बदलाव और जलवायु परिवर्तन।
भारत में बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई पहलें
- **बांध पुनर्संरचना और सुधार कार्यक्रम (DRIP):** यह बहु-चरणीय कार्यक्रम है, जिसे 2012 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। इसे 3 चरणों में लागू किया जा रहा है। इसमें बांधों में संरचनात्मक सुधार करने, बांध सुरक्षा का नियमित निरीक्षण करने तथा आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने पर बल दिया गया है।
- **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021:** यह सूचीबद्ध बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम के तहत 4-स्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया: राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, राज्य बांध सुरक्षा समितियाँ तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन।
अन्य पहलें:
- डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (DHARMA) प्लेटफॉर्म,
- सभी निर्धारित बांधों का मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात अनिवार्य निरीक्षण का प्रावधान।

--:16:--

आर्थिक घटनाक्रम

निर्वाह मजदूरी (Living Wage)

चर्चा में क्यों?

- नोएडा में कर्मकारों के विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत कर्मियों को "निर्वाह मजदूरी" प्रदान करने के राज्य के दायित्व को रेखांकित किया।



मुख्य बिन्दु:

- DPSP के तहत अनुच्छेद 43 यह निर्देश देता है कि राज्य सभी कर्मकारों के लिए "निर्वाह मजदूरी" और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

निर्वाह मजदूरी

- निर्वाह मजदूरी वह पारिश्रमिक है जो एक कर्मकार को एक मानक साप्ताहिक कार्य के लिए इतना प्राप्त हो कि वह अपने और अपने परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित कर सके।
- प्रायः, निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी से अधिक होती है।
- न्यूनतम मजदूरी, विधिक रूप से अनिवार्य वह न्यूनतम पारिश्रमिक होता है जो नियोक्ताओं को अपने कर्मकारों को अनिवार्य रूप से भुगतान करना होता है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

भारत और संयुक्त अरब अमीरात

चर्चा में क्यों?

- भारत के प्रधानमंत्री की UAE यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने 'रणनीतिक रक्षा साझेदारी (Strategic Defence Partnership) के लिए फ्रेमवर्क' पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिन्दु:

- यह फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग, नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, अभ्यास, शिक्षा और सिद्धांत, विशेष अभियान और इंटरऑपरेबिलिटी आदि को बढ़ावा देगा।



फ्रेमवर्क की अन्य मुख्य विशेषताएँ

- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को बढ़ावा: भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों (विशाखापत्तनम/चंडीखोल) में कच्चे तेल के भंडारण के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- **वाडीनार (गुजरात) में शिप रिपेयर क्लस्टर:** 'रिपेयर और ऑफशोर फेब्रिकेशन क्लस्टर' स्थापित करने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और ड्राइडॉक्स वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **मैत्री (MAITRI):** दोनों देशों ने मैत्री (मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस) का उपयोग करके वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के संचालन का स्वागत किया।

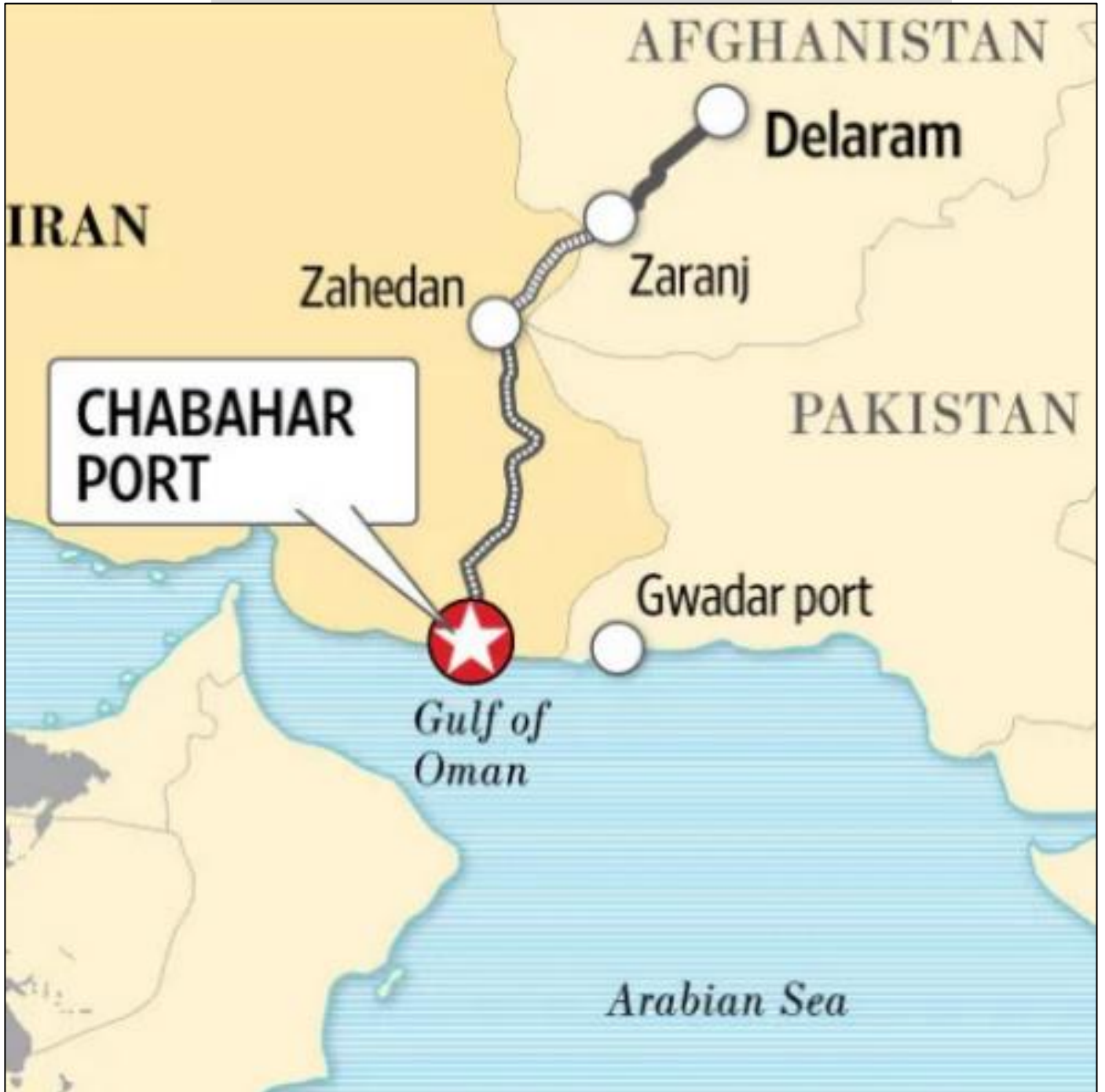
भारत-UAE संबंधों का महत्त्व

- **व्यापार और निवेश:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसे 2032 तक 200 बिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- UAE, भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंध व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) 2022, द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 और रुपये-दिरहम भुगतान व्यवस्था के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ तथा आसान बने हैं।
- **ऊर्जा:** UAE, भारत में कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता तथा LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। साथ ही, यह भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में भाग लेने वाला एकमात्र विदेशी सहभागी है।
- **रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग:** उदाहरण के लिए- दोनों देश I2U2 (भारत-इजराइल-यूएई-यूएसए) और UFI (यूएई-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय समूह का सदस्य हैं।
- **दोनों देशों के जन-समुदायों के बीच संपर्क:** UAE में 35 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यह समुदाय भारत में विप्रेषण में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

चाबहार बंदरगाह

चर्चा में क्यों?

- ईरान के विदेश मंत्री ने चाबहार बंदरगाह को भारत-ईरान सहयोग के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में रेखांकित किया और इसे मध्य एशिया का 'स्वर्ण द्वार' बताया।





मुख्य बिन्दु:

- वर्ष 2018 में, एक भारतीय कंपनी 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' ने चाबहार बंदरगाह के संचालन का कार्यभार संभाला था।
- वर्ष 2024 में, चाबहार बंदरगाह के 'शहीद बेहिश्ती टर्मिनल' के संचालन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

चाबहार बंदरगाह

- **अवस्थिति:** यह ओमान की खाड़ी में, दक्षिण-पूर्वी ईरान में मकरान तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।
- **दो टर्मिनल:** शहीद कलंतरी और शहीद बेहिश्ती।
- यह ईरान का एकमात्र बंदरगाह है, जिसे सीधे हिंद महासागर तक पहुंच प्राप्त है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का एक प्रमुख घटक है, जो भारत, मध्य एशिया और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के कारण प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

- हाल के एक अध्ययन के अनुसार 2019 के बाद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए सैटेलाइट्स की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण ऊपरी वायुमंडल में शक्तिशाली और दीर्घकालिक 'ब्लैक कार्बन' या कालिख का प्रदूषण हो रहा है।



मुख्य बिन्दु:

- ब्लैक कार्बन, सूक्ष्म कणिका वायु प्रदूषण (PM2.5) का एक घटक है। यह लकड़ी, अपशिष्ट और जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्सर्जित होता है।

Daily Current Affairs

Date : 18 May, 2026



वायुमंडल पर प्रभाव:

- कालिख के कणों का जमाव पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम कर रहा है। इस तरह यह एक प्रकार की जियो-इंजीनियरिंग की तरह कार्य कर रहा है।
- यह कालिख पृथ्वी पर मौजूद स्रोतों से निकलने वाली कालिख की तुलना में वायुमंडल की ऊपरी परतों में अधिक समय तक मौजूद रहती है। इसके परिणामस्वरूप जलवायु पर इसका 500 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है।
- सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण से वायुमंडल में क्लोरीन जैसे रसायन भी उत्पन्न हो सकते हैं जो ओजोन के साथ प्रत्यक्ष अभिक्रिया करके उसके क्षरण का कारण बन सकते हैं।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:23:--

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

पांचवीं पीढ़ी का उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA)

📢 चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री ने आंध्र प्रदेश में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) कार्यक्रम फैसिलिटी की आधारशिला रखी।



📌 मुख्य बिन्दु:

उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA)

- **स्वदेशी स्टील्थ फाइटर:** AMCA भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का मध्यम वजन वाला, स्टील्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है।
- **विकासकर्ता:** वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA), DRDO
- **वेरिएंट्स:** GE-F414 इंजन युक्त AMCA Mk1; स्वदेशी इंजन युक्त AMCA Mk2.

- **समय-सीमा:** प्रोटोटाइप 2028-29 तक तैयार हो जाने का अनुमान है और इसे 2034-35 तक सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की विशेषताएँ

- **दो इंजन:** ऐसे विमानों में एक इंजन खराब होने की स्थिति में दूसरा इंजन सक्रिय हो जाता है। इस तरह ये विमान उच्च स्तर की हवाई सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- **स्टीलथ क्षमताएँ:** यह रडार, इन्फ्रारेड और दृश्य संकेतों को कम करती हैं, जिससे दुश्मन द्वारा विमान का पता लगाना और उस पर हमला करना कठिन हो जाता है।
- **सुपर क्रूज़:** इसमें अधिक ईंधन खर्च करने वाले आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना, सुपरसोनिक गति (मैक 1 से अधिक) बनाए रखने की क्षमता है। इससे विमान की परिचालन सीमा और दक्षता में काफी वृद्धि होती है।
- **अन्य विशेषताएँ:** एकीकृत एवियोनिक्स, पायलट और विमान के बीच बेहतर समन्वय के लिए AI का उपयोग, तथा मजबूत नेटवर्किंग और संचार प्रणाली।
- वर्तमान में ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के उदाहरण: F-22 और F-35 (संयुक्त राज्य अमेरिका), सुखोई Su-57 (रूस), चेंगदू J-20 (चीन)।

5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA का सामरिक महत्त्व

- **भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण:** मिग-29 और मिराज विमानों के चरणबद्ध रूप से सेवा से हटने के बाद उत्पन्न महत्त्वपूर्ण क्षमता अंतर को भरने में मदद करेगा तथा भारतीय वायुसेना की घटती स्ववाङ्मन संख्या को फिर से मजबूत करेगा।
- **तकनीकी संप्रभुता:** विदेशी रक्षा प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता कम करेगा और 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से दीर्घकालिक रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।
- **आत्मनिर्भर भारत:** मजबूत घरेलू एयरोस्पेस औद्योगिक प्रणाली विकसित कर भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाएगा।

'अभय': एआई-संचालित सत्यापन प्रणाली

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सीबीआई नोटिसों के प्रमाणीकरण के लिए "अभय" नामक एक एआई-आधारित हेल्पबॉट लॉन्च किया है।

CBI LAUNCHES 'ABHAY'
AI-POWERED NOTICE VERIFICATION SYSTEM

REAL-TIME VERIFICATION
Verify authenticity of CBI notices in real time

AI-POWERED HELPBOT
Advanced AI detects genuine or fraudulent notices

EMPOWERING CITIZENS
Putting the power of verification in the hands of every citizen

HOW IT WORKS

- 1 Visit CBI's official website www.cbi.gov.in
- 2 Verify your mobile number with OTP
- 3 Upload a scanned copy of the notice
- 4 ABHAY AI analyzes and verifies the notice
- 5 Get instant result Genuine or Potentially Fraudulent

मुख्य बिन्दु:

'अभय'

- यह सीबीआई द्वारा जारी नोटिसों को सत्यापित करने के लिए जनता के लिए एआई-संचालित चैटबॉट-शैली का सत्यापन तंत्र है।
- इसे नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है।
- इसे डेटा की गोपनीयता और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रमाणीकरण तंत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।